

प्रारंभिक परीक्षा

धनप्रेषण प्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण बदलाव

संदर्भ

हाल ही में जारी आरबीआई धनप्रेषण सर्वेक्षण के अनुसार, उन्नत अर्थव्यवस्थाएं अब भारत में कुल धनप्रेषण का 50% से अधिक हिस्सा लाती हैं।

धनप्रेषण(Remittances) क्या है?

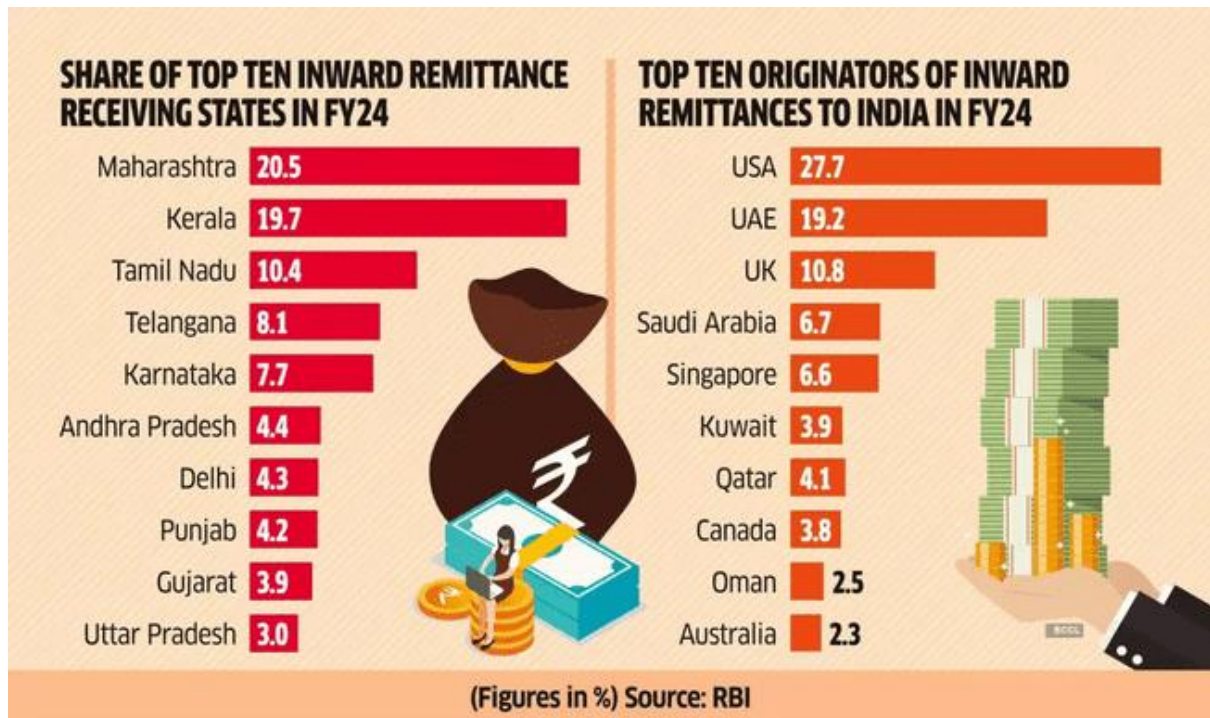
- धनप्रेषण, विदेश में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने देश में अपने परिवार या रिश्तेदारों को किया जाने वाला धन हस्तांतरण है।
- भारत के लिए, वे निम्नलिखित का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं: विदेशी मुद्रा भंडार, घरेलू आय सहायता और विकास वित्त।
- धनप्रेषण, भुगतान संतुलन (BoP) के चालू खाते में हस्तांतरण भुगतान श्रेणी के अंतर्गत आता है।
- भारत दुनिया में धनप्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता है।

आरबीआई के प्रेषण सर्वेक्षण (2023-24) की मुख्य विशेषताएं -

- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (AE) की हिस्सेदारी अब भारत में कुल प्रेषण का 50% से अधिक है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जिसकी 2023-24 में कुल प्रेषण में 27.7% हिस्सेदारी है।
- खाड़ी देशों की हिस्सेदारी लगातार घट रही है।

खाड़ी देशों से आने वाली धनराशि में गिरावट क्यों आ रही है?

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देश - संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान - उच्च भारतीय ब्लू-कॉलर प्रवास के कारण पारंपरिक रूप से शीर्ष स्रोत रहे हैं।
- गिरावट के कारण:
 - कोविड के बाद की आर्थिक मंदी: नौकरी छूटने और वेतन कटौती से धन प्रेषण क्षमता कम हो गई।
 - "राष्ट्रीयकरण" नीतियां: उदाहरण के लिए सऊदी अरब में सऊदीकरण/निताकत विदेशी श्रमिकों की तुलना में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देता है।
 - गिरता योगदान हिस्सा (2016-17 → 2023-24):
 - यूएई: 26.9% → 19.2%
 - सऊदी अरब: 11.6% → 6.7%
 - कुवैत: 6.5% → 3.9%



उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से धन प्रेषण में वृद्धि के पीछे कारण -

- प्रति व्यक्ति उच्चतर धन प्रेषण के कारण: उच्चतर वेतन, विशेष रूप से STEM, वित्त, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में
- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कुशल पेशेवरों का बड़ा भारतीय समुदाय।
- शैक्षिक प्रवास → व्यावसायिक रूप से बसना → प्रेषण।

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न: भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कारक मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में योगदानकर्ता है/हैं? (2019)

1. भारत के आईटी क्षेत्र की विदेशी मुद्रा आय
2. सरकारी व्यय में वृद्धि
3. विदेश में भारतीयों से प्राप्त धन

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

स्रोत: [Indian Express - Remittances](#)

NATO देश ओटावा संधि से हटने की योजना बना रहे हैं

संदर्भ

हाल ही में पोलैंड, फ़िनलैंड, बाल्टिक राज्यों (एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया) ने बारूदी सुरंग प्रतिबंध संधि (Mine Ban treaty) से हटने की योजना की घोषणा की है।

ओटावा संधि- 1997 के संदर्भ में -

- यह एक बहुपक्षीय संधि है, जिसका उद्देश्य विश्व भर में एंटी-पर्सनल लैंडमाइन को समाप्त करना है।
- इसे बारूदी सुरंग प्रतिबंध संधि (Mine Ban treaty) के नाम से भी जाना जाता है।
- संधि बारूदी सुरंगों के उपयोग, विकास और उत्पादन, भंडारण और अन्य राज्यों या समूहों को हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है।
- इसके अतिरिक्त, इसमें निम्नलिखित की आवश्यकता है:
 - 4 वर्षों के भीतर मौजूदा बारूदी सुरंग भंडारों को नष्ट करना।
 - 10 वर्षों के भीतर बारूदी सुरंग वाले क्षेत्रों को साफ करना।
 - पुनर्वास और पुनः एकीकरण सहित खनन पीड़ितों को सहायता।
- **सदस्यता:** 164 देश।
- **जो देश इसमें शामिल नहीं हुए हैं, वे हैं:** भारत, रूस, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और इज़राइल।
- अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC) और इंटरनेशनल कैम्पेन टू बैन लैंडमाइंस (ICBL) जैसे गैर सरकारी संगठनों ने, संधि की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **लैंडमाइन मॉनिटर** मुख्य निकाय है, जो अग्रलिखित पर दृष्टि रखता है: संधि का कार्यान्वयन, वैश्विक बारूदी सुरंग प्रदूषण आदि।

- 2024 की संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार- यूक्रेन विश्व में सबसे अधिक बारूदी सुरंग वाला देश है।

स्रोत: [Indian Express - Ottawa Convention](#)

स्टैंड अप इंडिया योजना

संदर्भ

हाल ही में स्टैंड अप इंडिया योजना को प्रारंभ हुए 9 वर्ष पूरे हो गए हैं।

स्टैंड अप इंडिया योजना के संदर्भ में -

- इसे आर्थिक सशक्तिकरण एवं रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था।
- उद्देश्य: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिलाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
- फोकस क्षेत्र: विनिर्माण, सेवा, व्यापार एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यमों को समर्थन प्रदान करना।
- ऋण राशि: 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये
- पात्रता मानदंड:
 - 18 वर्ष से अधिक आयु के SC/ST और/या महिला उद्यमी।
 - केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं (पहली बार के उद्यमों) के लिए ऋण।
 - गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के संदर्भ में, 51% स्वामित्व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिलाओं के पास होना चाहिए।
 - आवेदक किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।



स्रोत: [PIB - Stand Up India Scheme](#)

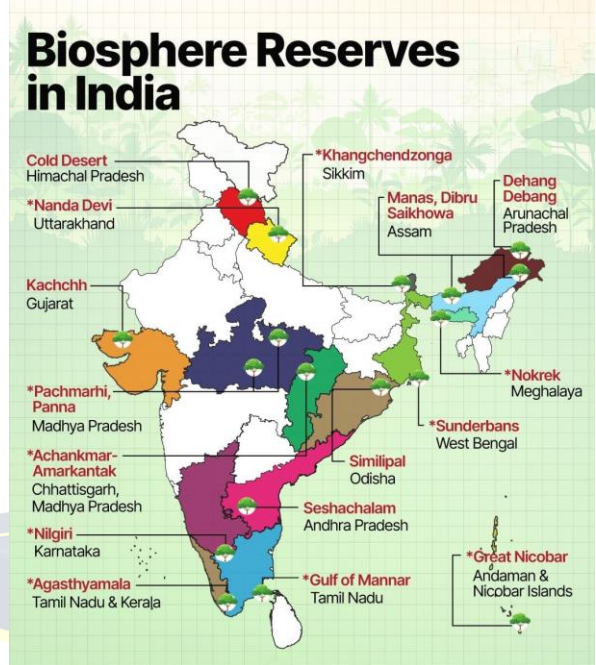
समाचार संक्षेप में

अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति(CEC) को अगस्त्यमाला परिदृश्य का व्यापक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है।

अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व (ABR) के संदर्भ में

- यह तमिलनाडु और केरल में दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है।
- इसका नाम, भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्णित पूजनीय ऋषि अगस्त्य के नाम पर रखा गया है।
- 2001 में इसे UNESCO बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था।
- जैव विविधता हॉटस्पॉट: अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व (ABR), पश्चिमी घाट-श्रीलंका जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है।
- बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर संरक्षित क्षेत्र:
 - कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व (KMTR) - तमिलनाडु
 - पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य - केरल
 - शेंदुरुनी वन्यजीव अभयारण्य - केरल
 - नेय्यार वन्यजीव अभयारण्य - केरल
 - श्रीविल्लिपुथुर ग्रीजल्ड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य - तमिलनाडु
 - मेघमलाई और थिरुनेलवेली वन्यजीव अभयारण्य - तमिलनाडु



स्रोत: [The Hindu - ABR](#)

पोषण ट्रैकर

- हाल ही में, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने घोषणा की है कि- सम्पूर्ण भारत के सभी आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन पर पंजीकृत हैं।

पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के संदर्भ में -

- यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले पोषण मिशन की प्रगति की निगरानी एवं ट्रैक करने के लिए, एक मोबाइल एप्लिकेशन है।
- इसका उद्देश्य पोषण सेवा वितरण में पारदर्शिता, दक्षता एवं जवाबदेही को बढ़ाना है।
- यह मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का हिस्सा है।

स्रोत: [DD News - Poshan tracker](#)



वारंगल चपाता मिर्च

- हाल ही में, तेलंगाना की वारंगल चपाता मिर्च को GI (भौगोलिक संकेत) टैग प्रदान किया गया है।

- यह अपने चमकीले लाल रंग और हल्के तीखेपन के लिए जाना जाता है, जो इसे अचार निर्माताओं के बीच पसंदीदा विकल्प बनाता है।
- इसे टोमेटो चिली भी कहा जाता है, क्योंकि इसका गोल आकार टमाटर जैसा होता है।

स्रोत: [The Hindu - Warangal Chapata](#)

बाकू से बेलेम रोडमैप

- भारत ने हाल ही में BRICS पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के दौरान, BRICS देशों से 'बाकू से बेलेम रोडमैप' पर एकजुट होने का आग्रह किया है।

बाकू से बेलेम रोडमैप के संदर्भ में -

- यह 2024 में बाकू, अजरबैजान में आयोजित 29 वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP29) के दौरान स्थापित, एक पहल है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य, विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्तपोषण को बढ़ाना है।
- इसका लक्ष्य कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु-लचीले विकास मार्गों का समर्थन करने के लिए, 2035 तक वार्षिक रूप से कम से कम 1.3 ट्रिलियन डॉलर एकत्र करना है।

स्रोत: [Times of India - Baku to Belem roadmap](#)

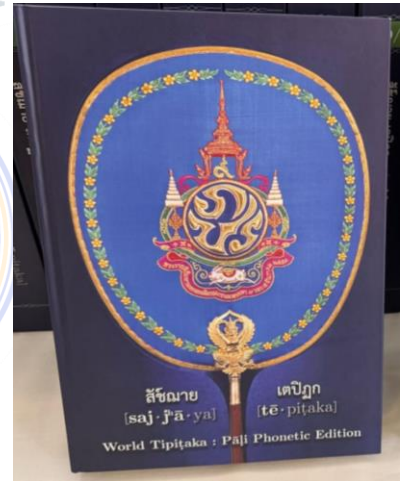
त्रिपिटक

- थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान, भारतीय प्रधानमंत्री को पाली भाषा में त्रिपिटक की एक प्रति उपहार में दी है।

त्रिपिटक के संदर्भ में -

- यह थेरवाद बौद्ध धर्म का प्रामाणिक धर्मग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं सम्मिलित हैं।
- त्रिपिटक (तीन टोकरीयाँ) की संरचना:
 - विनय पिटक:
 - इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम और आचरण शामिल हैं।
 - पातिमोक्ख- मठवासी अनुशासन की एक संहिता, विनय पिटक का हिस्सा है।
 - सुत्त पिटक:
 - इसमें बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश शामिल हैं।
 - 5 निकायों (संग्रह) में विभाजित: दीघ निकाय, मज्झिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय।
 - अभिधम्म पिटक:
 - इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण शामिल है।
- हाल ही में पाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है।

स्रोत: [PIB - Tripitaka](#)



हंसा-3 (अगली पीढ़ी - NG)

- हाल ही में, पायनियर क्लीन AMPS प्राइवेट लिमिटेड ने हंसा-3 विमान के उत्पादन के लिए, एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते (ToT) पर हस्ताक्षर किए हैं।

हंसा-3 के संदर्भ में -

- यह एक ट्विन-सीटर स्वदेशी नागरिक विमान है, जिसे नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (NAL), बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है।

- नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (NAL), CSIR (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद) के तहत कार्य करता है।
- **उपयोग:** मुख्यतः पायलट प्रशिक्षण, मनोरंजक उड़ान और वायुगतिकीय अनुसंधान के लिए।
- यह हंसा श्रृंखला का नवीनतम संस्करण है, जो 1998 में प्रारंभ हुआ था।
- यह पहली बार है, जब विमान का निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके, भारत में किया जाएगा।

स्रोत: [Deccan Herald - HANSA - 3](#)

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II (VVP-II)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II को स्वीकृति दे दी है।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II के संदर्भ में -

- **VVP-II एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है (100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित)।**
 - VVP-I, एक केंद्र प्रायोजित योजना थी।
- इसे निम्नलिखित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा गांवों में लागू किया जाएगा:
 - **पूर्वोत्तर:** अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा।
 - **उत्तर:** जम्मू एवं कश्मीर (UT), लद्दाख (UT), पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश।
 - **पूर्व:** बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश।
 - **पश्चिम:** राजस्थान, गुजरात
- VVP-II, VVP-I पर आधारित है, जो केवल उत्तरी सीमा के गांवों पर केंद्रित है।
- **VVP-II के उद्देश्य:**
 - सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास।
 - जीवन स्थितियों और आजीविका के अवसरों में सुधार।
 - समृद्ध एवं सुरक्षित सीमाएँ सुनिश्चित करना और सीमा पार अपराध पर नियंत्रण रखना।
 - ग्रामीणों को सीमा सुरक्षा बलों की "आंख और कान" के रूप में शामिल करना।
- कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति, योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

स्रोत: [PIB - VVP](#)

डेयर-अल-बलाह

- हाल ही में गाजा के डेयर अल बलाह स्थित एक स्कूल पर इजरायल द्वारा किए गए हमले में बच्चों और महिलाओं सहित लगभग 31 लोग मारे गए।
- डेयर अल-बलाह मध्य गाजा पट्टी में एक फिलिस्तीनी शहर है।
- यह फिलिस्तीन राज्य के देयर अल-बलाह प्रांत की प्रशासनिक राजधानी है।
- यह गाजा शहर से 14 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है।
- यह शहर अपने खजूर के पेड़ों के लिए जाना जाता है, जिसके नाम पर इसका नाम खजूर रखा गया है।
- डेयर अल-बलाह शरणार्थी शिविर गाजा पट्टी का सबसे छोटा शरणार्थी शिविर है।



स्रोत: [The Hindu - Dier Al Balah](#)

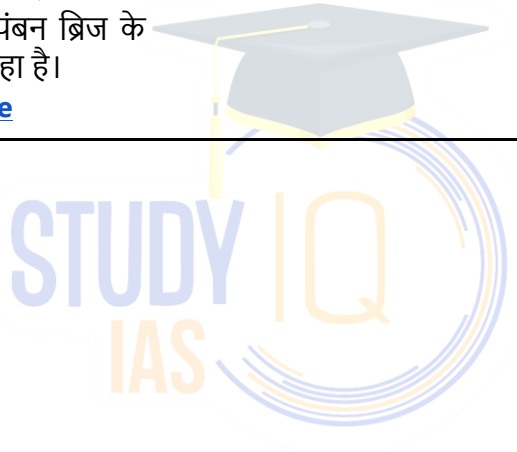
नया पम्बन ब्रिज

● प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रामनवमी के अवसर पर नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे।
नए पम्बन ब्रिज के बारे में -

- यह भारत का पहला वर्टिकल-लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है।
- यह पुल 2.05 किलोमीटर लंबा है, जिसमें जहाज की आवाजाही के लिए 72 मीटर का अनोखा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है।
- यह पंबन द्वीप पर रामेश्वरम को तमिलनाडु में मुख्य भूमि पर मंडपम से जोड़ता है।
- यह भारत के पहले समुद्री पुल, प्रतिष्ठित पंबन ब्रिज की जगह लेगा, जिसे 1914 में खोला गया था।
- नया पुल रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा पुराने पंबन ब्रिज के समानांतर बनाया जा रहा है।



स्रोत: [PIB - Pamban Bridge](#)



संपादकीय सारांश

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ

संदर्भ

31 मार्च को मनाया जाने वाला **अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस**, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समक्ष चुनौतियाँ -

- **सामाजिक बहिष्कार और कलंक:** लगातार सामाजिक पूर्वाग्रह, पारिवारिक अस्वीकृति और सीमांत पर रहना।
 - स्कूलों में धमकाने और उत्पीड़न के कारण स्कूल छोड़ने की दर उच्च हो गई है (उदाहरण के लिए- केरल में **58%** ड्रॉपआउट)।
- **कानूनी और नौकरशाही बाधाएँ:** ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, **2019** के तहत, पहचान पत्र जारी करने में देरी।
 - जटिल नौकरशाही प्रमाणन प्रक्रिया, आत्म-पहचान को कमजोर करती है।
- **आर्थिक भेदभाव:** **92%** को आर्थिक गतिविधि से बाहर कर दिया गया (NHRC, 2018); कई लोगों को देह व्यापार में धकेल दिया गया।
 - राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्च बेरोजगारी दर (2022 में 48%)
 - भर्ती के दौरान पक्षपात, लिंग-तटस्थ सुविधाओं की कमी, कार्यस्थल पर शत्रुता।
- **शैक्षिक असमानताएँ:** ट्रांसजेंडर साक्षरता दर: 56.1% (2011 जनगणना) बनाम 74.04% राष्ट्रीय औसत।
 - समावेशी पाठ्यक्रम की कमी और संस्थानों में भेदभाव के कारण ड्रॉपआउट।
- **स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच के मुद्दे:** उपचार से इनकार (लिंग पहचान के कारण 27% ने देखभाल से इनकार कर दिया)।
 - लिंग-पुष्टि सर्जरी (Gender-affirming surgeries) महंगी होती है तथा प्रायः बीमा के अंतर्गत कवर नहीं होती है।
 - मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ सीमित हैं और पेशेवरों के पास प्रशिक्षण का अभाव है।

सरकारी पहल और उनकी खामियां -

कानूनी ढांचा

- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019**
 - पहचान की कानूनी मान्यता।
 - शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल में भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है।
 - **कमियाँ:** विलंबित प्रमाणीकरण, प्रवर्तन तंत्र की कमी, पुलिस उत्पीड़न और परिवार द्वारा अस्वीकृति जैसे मुद्दों की अनदेखी।

कल्याण एवं वित्तीय योजनाएँ

- पहचान आवेदनों के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल।
 - लेकिन दिसंबर **2023** तक केवल **~66%** प्रमाणपत्र जारी किए गए; कई में विलंब हुआ।
- **5 लाख रुपये वार्षिक कवरेज** के लिए, आयुष्मान भारत **TG** प्लस कार्ड।
 - **कमियाँ:** कम जागरूकता, खराब कार्यान्वयन, मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवाओं से बहिष्कार।
- **2024:** वित्त मंत्रालय **LGBTQ+** के संयुक्त बैंक खाते और नामांकन की अनुमति प्रदान करता है।
 - **कमियाँ:** वित्तीय सेवाओं में अभी भी व्यापक समावेशिता का अभाव है।

राज्य स्तरीय पहल

- **महाराष्ट्र:** कॉलेजों में ट्रांसजेंडर सेल।
- **केरल:** विश्वविद्यालयों में आरक्षित सीटें, समर्पित छात्रावास।

- **कमी:** राष्ट्रीय स्तर पर कोई दोहराव नहीं; सीमित प्रभाव।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाने के लिए कदम -

- **नीति कार्यान्वयन को मजबूत करना:**
 - पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल और तीव्र करना।
 - प्रभावी शिकायत निवारण और भेदभाव विरोधी कानूनों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करना।
 - पुलिस उत्पीड़न और परिवार आधारित बहिष्कार के खिलाफ विशिष्ट सुरक्षा शामिल करना।
- **आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना:** उद्योगों में विविधतापूर्ण भर्ती नीतियाँ (जैसा कि टाटा स्टील में देखा गया है)।
 - ट्रांसजेंडर उद्यमियों के लिए सरकार समर्थित ऋण सुविधा प्रदान करना।
 - लक्षित कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण।
 - प्रतीकात्मक सुधारों से परे समावेशी वित्तीय सेवाएँ।
- **शिक्षा तक पहुँच में सुधार:** लैंगिक-संवेदनशील पाठ्यक्रम शुरू करना।
 - स्कूलों और कॉलेजों में बदमाशी विरोधी तंत्र।
 - ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और छात्रावास सुविधाएँ।
- **स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बेहतर बनाना:** ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य पर चिकित्सा पेशेवरों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण।
 - सार्वजनिक और निजी बीमा के तहत लैंगिक-पुष्टि प्रक्रियाओं का कवरेज।
 - समर्पित ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापित करना और मानसिक स्वास्थ्य सहायता को मजबूत करना।
- **सामाजिक स्वीकृति को बढ़ावा देना:** गैर-रूढ़िवादी भूमिकाओं में मीडिया की भूमिका।
 - सांस्कृतिक समावेशन (उदाहरण के लिए, कूवगम महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना)
 - 'मैं भी इंसान हूँ' जैसे जागरूकता अभियान।
 - स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रम।

स्रोत: [The Hindu: A people still waiting to move out of the margins](#)

विस्तृत कवरेज

क्या भारत को अमेरिका के कदमों को देखते हुए टैरिफ कम करना चाहिए?

संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 अप्रैल को सभी प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ "पारस्परिक टैरिफ" की घोषणा करके अमेरिका के "मुक्ति दिवस" का उत्सव मनाया।

समाचार के बारे में और अधिक जानकारी -

- टैरिफ के दो समूह घोषित किए गए थे।
 1. सभी देशों के खिलाफ **10%** का आधार टैरिफ (पहले **2.5%**)।
 2. देश-विशिष्ट टैरिफ।

पारस्परिक टैरिफ क्या है?

- पारस्परिक टैरिफ, दूसरे देशों से आयात पर टैरिफ लगाने की पद्धति को संदर्भित करता है, जो उन देशों द्वारा पारस्परिक टैरिफ लगाने वाले देश से आयात पर लगाए गए टैरिफ से संरक्षित होता है।
 - उदाहरण के लिए, यदि देश **A** देश **B** से आयात पर **10%** टैरिफ लगाता है, तो देश **B** भी देश **A** से आयात पर **10%** टैरिफ लगा सकता है।

टैरिफ क्या है?

- टैरिफ या प्रशुल्क एक ऐसा कर है जो एक देश द्वारा दूसरे देश से आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर राजस्व बढ़ाने, घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने या दूसरे देश पर राजनीतिक प्रभाव डालने के लिए लगाया जाता है।

टैरिफ के लाभ और दोष

लाभ	दोष
राजस्व उत्पन्न करता है	सरकारों के बीच संघर्ष के मुद्दे पैदा होते हैं
खुली बातचीत के अवसर पैदा करता है	व्यापार युद्ध शुरू करता है
राष्ट्र के लक्ष्यों का समर्थन करता है	
बाज़ार को पूर्वानुमान योग्य बनाता है	

पारस्परिक टैरिफ लगाने के पीछे कारण -

- **घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना:** पारस्परिक टैरिफ का उद्देश्य आयातित वस्तुओं को अधिक महंगा बनाना है, जिससे कंपनियों को अपनी उत्पादन सुविधाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- **रोजगार सृजन और वेतन वृद्धि:** स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर, प्रशासन का लक्ष्य देश के भीतर अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना और अमेरिकी श्रमिकों के लिए संभावित रूप से वेतन बढ़ाना है।
- **बातचीत की रणनीति के रूप में:** टैरिफ अन्य देशों को व्यापार वार्ता में धकेलने के लिए दबाव उपकरण के रूप में काम करते हैं।
- **अनुचित व्यापार प्रथाओं का विरोध करना:** अमेरिकी प्रशासन का सुझाव है कि यदि व्यापारिक भागीदार अनुचित व्यापार प्रथाओं को हटाने या व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए सहमत होते हैं तो टैरिफ कम या समाप्त किए जा सकते हैं।

- **व्यापार घाटे की समस्या का समाधान करने के लिए:** टैरिफ का उद्देश्य विशिष्ट देशों के साथ अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करना भी है। आयात को हतोत्साहित करके और निर्यात को प्रोत्साहित करके, नीति व्यापार प्रवाह को फिर से संतुलित करने का प्रयास करती है।

Country	Trump estimates of tariffs on US goods	Trump's 'reciprocal' tariffs	US trade deficit in 2024 (with a minus sign) in \$ millions	US Trade Deficit as a percentage of the total US Trade deficit	Per capita income (US is at \$ 89,680)
Cambodia	97%	49%	-12,300	1.0	\$ 2,950
Vietnam	90%	46%	-1,22,071	10.1	\$ 4,990
Sri Lanka	88%	44%	NA	NA	NA
Bangladesh	74%	37%	-6,152	0.5	\$ 2,770
Thailand	72%	36%	-45,609	3.8	\$ 7,750
China	67%	34%	-2,95,402	24.6	\$ 13,870
Taiwan	64%	32%	-73,937	6.1	\$ 34,920
Indonesia	64%	32%	-17,883	1.5	\$ 5,250
Switzerland	61%	31%	-38,463	3.2	\$ 1,11,720
South Africa	60%	30%	-8,837	0.7	\$ 6,520
Pakistan	58%	29%	-2,989	0.2	NA
India	52%	26%	-45,664	3.8	\$ 2,940
South Korea	50%	25%	-66,007	5.5	\$ 37,670
Japan	46%	24%	-68,468	5.7	\$ 35,610
Malaysia	47%	24%	-24,830	2.1	\$ 14,420
EU	39%	20%	-2,31,769	19.3	\$ 45,240
Israel	33%	17%	-7,425	0.6	\$ 54,370
Philippines	34%	17%	-4,880	0.4	\$ 4,440
UK	10%	10%	11,857	-1.0	\$ 54,280
Brazil	10%	10%	7,351	-0.6	\$ 10,820
Singapore	10%	10%	2,829	-0.2	\$ 93,960
Chile	10%	10%	NA	NA	\$ 17,930
Australia	10%	10%	-73,927	6.1	\$ 67,980
Turkey	10%	10%	-1,453	0.1	\$ 16,880
Colombia	10%	10%	1,347	-0.1	\$ 7,900
World			-12,02,872		\$ 14,450

Source: White House, IMF, Indian Express Research

अमेरिकी पारस्परिक प्रशुल्कों पर अन्य देशों की प्रतिक्रियाएँ क्या हो सकती हैं

- **प्रतिशोध:** अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं पर समान दर से या अधिक टैरिफ अधिरोपित करना।
 - उदाहरण के लिए, इसके प्रत्युत्तर में चीन ने अमेरिकी वस्तुओं के सभी आयातों पर **34%** टैरिफ लगा दिया।
 - **चुनौतियाँ:**
 - **आर्थिक रूप से हानिकारक** - अमेरिकी प्रशुल्कों के समान ही नकारात्मक प्रभाव।
 - केवल **भारत, चीन या यूरोपीय संघ जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ** ही अमेरिकी निर्यात में महत्वपूर्ण कमी ला सकती हैं।
 - अमेरिका द्वारा आगे और वृद्धि को उकसाया जा सकता है (उदाहरण के लिए, फार्मा या सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर टैरिफ)।
 - राजनीतिक रूप से अप्रभावी, क्योंकि वर्तमान अमेरिकी प्रशासन इसे वापस लेने को कमज़ोरी के संकेत के रूप में देखता है।
- **निर्यात को पुनः उन्मुख करना और नए बाज़ार ढूँढना:** अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए निर्यात गंतव्यों में विविधता लाना।
 - **रणनीतियाँ:** बाज़ार अनुसंधान और नई व्यापार भागीदारी।

- **व्यापार समझौतों में तेज़ी लाना, जैसे:**
 - AfCFTA (अफ्रीका)
 - EU-Mercosur समझौता
 - भारत-श्रीलंका FTA
- **अमेरिका के साथ बातचीत:** देश अपने **MFN** (सबसे पसंदीदा राष्ट्र) टैरिफ या व्यापार नीतियों को अमेरिकी अपेक्षाओं के अनुरूप समायोजित कर सकते हैं।
 - बांग्लादेश, श्रीलंका या फ़िजी जैसे देश अमेरिकी वस्तुओं पर अपने टैरिफ कम कर सकते हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पारस्परिक शुल्क का प्रभाव -

- **वैश्विक व्यापार में व्यवधान:** पारस्परिक शुल्क स्थापित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ाते हैं, और व्यापार की मात्रा को कम करते हैं।
 - उदाहरण के लिए, वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया और श्रीलंका जैसे देशों को कपड़ों और जूतों जैसे प्रमुख निर्यातों पर **भारी शुल्क (54% तक)** का सामना करना पड़ता है। ये देश अपने निर्यात के **25%** से अधिक के लिए **अमेरिकी बाजार पर** अत्यधिकनिर्भर हैं।
- **अमेरिकी आयात स्रोतों में बदलाव (व्यापार विचलन):** अमेरिका में तरजीही व्यापार पहुँच वाले देश - जैसे केन्या, इथियोपिया (**AGOA** के तहत), और निकारागुआ (**CAFTA-DR** के माध्यम से) - बाजार हिस्सेदारी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि अमेरिकी खरीदार उच्च-शुल्क वाले एशियाई आपूर्तिकर्ताओं से दूर हो सकते हैं।
- **मुद्रास्फीति में वृद्धि:** टैरिफ आयातित वस्तुओं की कीमत में वृद्धि करते हैं, जिससे आयात करने वाले और निर्यात करने वाले दोनों देशों में मुद्रास्फीति का दबाव होता है।
 - **अमेरिका में:** उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और ऑटो पार्ट्स जैसी वस्तुओं के लिए अधिक भुगतान करते हैं।
 - **वैश्विक स्तर पर:** प्रतिशोधात्मक शुल्कों के कारण कमज़ोर मुद्रा से प्रभावित देशों को महंगे आयात का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से कच्चे तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं का।
- **मुद्रास्फीतिजनित मंदी का जोखिम:** जब उच्च मुद्रास्फीति स्थिर या नकारात्मक वृद्धि के साथ संरक्षित होती है - जिसे **मुद्रास्फीतिजनित मंदी (stagflation)** के रूप में जाना जाता है - तो यह विशेष रूप से कठिन नीतिगत चुनौती पैदा करती है।
 - केंद्रीय बैंकों को बेरोज़गारी को बढ़ाए बिना या विकास को और अधिक बाधित किए बिना मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।
 - निवेश की भावना कमज़ोर होती है, जिससे विकास और बाधित होता है।
- **अनिश्चितता और निवेशकों का पीछे हटना:** टैरिफ युद्ध वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता लाते हैं, जिससे दीर्घकालिक निवेश में बाधा आती है।
 - अनिश्चित आय परिदृश्य के कारण शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है।
 - अप्रत्याशित व्यापार नीति परिवेश के कारण फर्म विस्तार योजनाओं या भर्ती में देरी कर सकती हैं।
- **वैश्विक गठबंधनों और व्यापार ब्लॉकों में बदलाव:** पारस्परिक टैरिफ, वैकल्पिक व्यापार ब्लॉकों के गठन या क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करने में तेज़ी ला सकते हैं।
 - **यूरोपीय संघ और एशिया,** अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने के लिए अधिक निकटता से जुड़ सकते हैं।
 - **भारत और आसियान** वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभर सकते हैं यदि वे कम व्यापार बाधाओं को बनाए रखते हैं।
- **मुद्रा वॉर की संभावना:** टैरिफ प्रभावों को ऑफसेट करने के लिए, देश निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए जानबूझकर अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन कर सकते हैं।
 - **परिणाम:** प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन से उभरते बाजारों में मुद्रा अस्थिरता, पूंजी पलायन और आर्थिक आघात की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

भारत के लिए क्या अवसर हैं?

अवसर क्षेत्र	विवरण
सापेक्ष टैरिफ लाभ	भारत को 26% टैरिफ का सामना करना पड़ता है, जो चीन (54%), वियतनाम (46%), बांग्लादेश (37%) से कम है - कपड़ा और परिधान जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
मूल्य-वर्धित विनिर्माण	भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में उच्च कीमतों को उचित ठहराने के लिए गुणवत्ता, नवाचार और ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
व्यापार विविधीकरण	भारत को यूरोपीय संघ, आसियान, अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसे वैकल्पिक निर्यात बाजारों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है।
आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरक्षण	भारत चीन से दूर विविधता लाने के इच्छुक वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित कर सकता है (चीन + 1 रणनीति)।
एमएसएमई क्षेत्र उन्नयन	टैरिफ दबाव MSMEs में औपचारिकता, डिजिटल परिवर्तन और उत्पादकता को बढ़ावा दे सकता है।
रणनीतिक कूटनीति	भारत-अमेरिका व्यापार, सेवाओं और निवेश ढांचे में बेहतर शर्तों पर बातचीत करने के लिए स्थिति का लाभ उठाना।

स्रोत: [Indian Express: rump's reciprocal tariffs — impact on India, rest of the world](#)